International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 5, May- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

समावेशी विकास में स्थानीय स्वशासन की भूमिका

संजय कुमार कनौजिया
शोधार्थी, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज0)
डॉ0 आलोक कुमार श्रीवास्तव
आचार्य – राजनीति विज्ञान (राज0 महाविद्यालय, अजमेर)
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

लेखसार:– भारतीय संस्कृति समय के साथ न केवल निरन्तर गतिमान है बल्कि इसकी मूल अवधारणा भी उतनी ही शाश्वत एवं सत्य है जितनी की मानवीय इतिहास की अवधारणा है । भारत की इस मूल अवधारणा में सदैव स्वस्थ एवं सुखि समाज के दृष्टिकोण को समावेशित किया है । भारत में लोकतान्त्रिक मूल्यों के साथ–साथ सत्ता को निचले स्तर तक पहुँचाने एवं स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु स्थानीय स्वशासन के मार्ग को अपनाया गया है जो न केवल स्थानीय समस्याओं को सुलझाने का कार्य करता है बल्कि शासन व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं, नितियों कार्यक्रमो, अभियानो, वित्तिय प्रबन्धन आदि विभिन्न क्षेत्रो विकास के व्यापक दृष्टिकोण के साथ अग्रसर रहता है जिसमें सबके हित एवं लोक कल्याण के उद्देश्यों से पिछड़ो एवं गरीबों को साथ लेकर कार्य किया जाता हैं तब हम समावेशी विकास के मूल भाव तक पहुँच पाते हैं ।

मुख्य शब्द:– अवधारणा, स्वशासन, समावेशी, नवसृजित, विकेन्द्रीकरण, संसाधन, कौशल, समृद्ध, वैश्विक, बुनयादि, निराकरण, भौतिक, शाश्वत, द्रष्टिकोण, प्रबन्ध ।

प्रस्तावना:–

भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति है जो समय के साथ निरन्तर गतिमान है इस संस्कृति की मूल अवधारणा का इतिहास भी अत्यन्त प्राचीन है । इस संस्कृति में लोकतान्त्रिक मूल्यों, आदर्शो, विचारों, सिद्धान्तो, अवधारणाओं आदि को प्रमुखता के साथ हमारी जीवन शैली में देखा जाता है जो सदेव स्वस्थ, सुखी, सम्पन्न समाज उद्देश्य को स्थापित करने का प्रयास करती है। 'यहां सर्वे भवन्तु सुखिन' की मूल भाव के आधार पर कार्य सम्पादित होते है जो समावेशी विकास की झलक करता है समावेशी विकास तेजी से उभरता हुआ नवसृजीत मांग है जिसमें सबे हित एवं कल्याण के भाव को प्रधानता प्राप्त होती है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, विभिन्न समस्याओं का निराकरण, सबको साथ लेकर विकास के पथ पर आगे बढ़ा जायें । यही समावेशी विकास का मूल भाव हैं।

स्थानीय स्वशासन भी समावेशी विकास के इन उद्देश्यों की प्राप्ती हेतु हम निरन्तर सक्रिय है जो स्वस्थ समाज के मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण करता हैं ।

आज के वैश्विक दौर में जहाँ हमारी जीवन शैली में विभिन्न उथल–पुथल भरी हुई है यहां इस लिये सबके हित एवं कल्याण के लिये एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समावेशी विकास का मार्ग निरन्तर प्रवाहित रहता हैं ।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 5, May- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

वर्तमान समय में स्थानीय स्वशासन के कार्य क्षेत्रों निरन्तर विस्तार हो रहा है जैसे–जैसे समावेशी विकास की मांग बढ़ती जा रही है यह मांग केवल स्थानीय स्वशासन के द्वारा ही पूर्ण की जा सकती हैं ।

अध्ययन के उद्देश्यः–

1– समावेशी विकास की आवश्यकता का अध्ययन करना ।

2– समावेशी विकास के द्वारा होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना ।

3– स्थानीय स्वशासन एवं समावेशी विकास के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करना ।

4– स्थानीय स्वशासन के द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों का प्रभाव एवं महत्व का अध्ययन कराना ।

समावेशी विकास का अर्थः–

समावेशी विकास एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें सभी व्यक्तियों के लिये अवसरों की समानता हो साथ ही सभी को साथ लेकर विशेषकर गरीब एवं पिछड़े लोगो को साथ जोड़ते हुए सभी के हित, कल्याण, उन्नति के लिये कार्य हो एवं सभी व्यक्तियों को रोजगार और कौशल के नये अवसरो की उपलब्धता हो यही समावेशी विकास का मूल भाव हैं ।

समावेशी विकास की आवश्यकताः–

(1) सभी क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करने हेतु ।

(2) गरीब एवं पिछड़े लोगो की सहायता एवं उन्नति हेतु ।

(3) विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ।

(4) बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ।

(5) रोजगार एवं कौशल के अवसरों की उपलब्धता हेतु ।

स्थानीय स्वशासन की भूमिकाः–

भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है जो सदैव स्थानीय समस्याओं के निराकरण और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सजग रहा है । लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के मार्ग अपनाने के बाद शासन न केवल निचले स्तर तक पहुंचा है बल्कि भौतिक एवं अन्य संसाधनो की उपलब्धता भी निरन्तर बढ़ी हैं ।

स्थानीय स्वशासन में विभिन्न नितियों, योजनाओं, कार्यक्रमों अभियानो एवं वित्तिय प्रबन्धनों द्वारा स्थानीय समस्याओं के निराकरण, बुनियादी आवश्यकताओं की समयबुद्ध पूर्ति, लोकतान्त्रिक मूल्यों की मजबूती, जनकल्याण, विकास आदि को

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 13 Issue 5, May- 2023
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

तीव्रगति प्रदान हुई है जिसके कारण आज के दैनिक जीवन एवं वैश्विक दौर विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु जो भी सार्थक प्रयास किय जा रहे है और यह प्रयास प्रायः जीवन के सभी क्षेत्रो निरन्तर जारी है जिसके कारण समावेशी विकास के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ती सम्भव हो सकी है । जिसके कारण आज हम समावेशी विकास के इस दौर में मजबूती से उपलब्ध हैं ।

सन्दर्भः–

1– बाला डॉ0 सरोज : स्थानीय प्रशासन (1995)
राज0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

2– कुमार डॉ0 अनिल : भारत के विकास में चुनौतियॉ (2012)
महेन्द्र बुक कम्पनी, गुड़गॉव

3– श्री चरण : पंचायती राज एवं लोकतन्त्र (2001)
पंकज पुस्तक मन्दिर, दिल्ली

4– शर्मा डॉ0 हरीशचद: भारत में स्थानीय प्रशासन (2006)
कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

5– त्रिपाठी डॉ0 धनंजय कुमार :ग्रामीणतथा नगरीय समाज शास्त्र (2008)
विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी

- ✔ योजना नई दिल्ली–जून 2016, मई 2017
- ✔ प्रतियोगिता दर्पण नई दिल्ली–अक्टूबर, 2017
- ✔ प्रतियोगिता दृष्टि नई दिल्ली–फरवरी, 2016

www.rajkaushal.rajasthan.gov.in

www.urban.rajasthan.gov.in

www.panchayatiraj.gov.in